आवश्यकता

प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय स्तर के संगठन में पत्रकारों की प्रमुख समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्य करने वाले पत्रकारों को एसोसिएशन सक्रिय सदस्य एवं साधारण सदस्य बनाकर योग्य कमलकारों को राष्ट्रीय, प्रान्तीय / मंडलीय / जिलास्तरीय पदाधिकारी नियुक्त करता है। इच्छुक पत्रकार संपर्क करें।

गिरिश चंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रिन्ट एवं इलेक्टॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन (भारत)

मोबाइल नंबर 9515174838

हरदोई,लखनऊ एवं कासगंज से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

सहानुभूति

E-Mail : sahanubhutinews@gmail.com

R.N.I NO - UPHIN/2008/27700

वर्ष –19
अंक – 30
हरदोई
शनिवार, 30 अगस्त 2025 पृष्ठ – 04
मूल्य – 02 रूपये

हर खिलाड़ी समाज का हीरो है : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। हर खिलाड़ी समाज के लिए हीरो होता है। हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ने, खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, समन्वय स्थापित करने और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। सही मायनों में खिलाड़ियों से समाज को समर्पण की प्रेरणा मिलती है। यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो खेल दिवस के अवसर पर पदमश्री मो. शाहिद स्टेडियम में प्रदेश के राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देने आए। इस अवसर पर उन्होंने नौ सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए। साथ ही प्रदेश के पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सीएम ने स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच खेले गए मैत्री मुकाबले का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है तो हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है। 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर उन्होंने भारत की हॉकी को वैश्विक पहचान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार किसी नेता नहीं, बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए यह इसलिए भी गौरव की बात है क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है। उनकी स्मृति में मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किया गया है और इस सत्र से वहां पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है। विभिन्न खेलों के लिए इन कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। पूर्व ओलंपियनध कॉमनवेल्थधएशियाडधनेशनल गेम्स मेडलिस्टों को कोच बनाकर नई प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, हर विकासखंड पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है। ओपन जिम के निर्माण व युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हॉकी में अनेक दिग्गज दिए हैं। मेजर ध्यानचंद, के. डी. सिंह 'बाबू', मोहम्मद शाहिद, रवींद्र पाल, सैयद अली, डॉ. आर. पी. सिंह, सुजीत कुमार, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एम. पी. सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, रितुषा कुमारी आर्या जैसे हॉकी खिलाड़ियों प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया।

पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द के लिए माफी मांगें राहुल गांधी, कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह

गुवाहाटी , (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में विपक्षी गठबंधन के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की घटना की निंदा की। शाह ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बेहद निंदनीय कृत्य किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। शाह ने कहा, श्दो दिन पहले जो हुआ, उससे सभी को दुख पहुंचा है। पीएम मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया, अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। ऐसे जीवन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी कोई गिरावट नहीं हो सकती और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।श उन्होंने आगे कहा, श्मैं राहुल गांधी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें पीएम मोदी, दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। इससे पहले चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया।

संक्षिप्त खबरें

हर परिवार की एक महिला को मिलेंगे 10 हजार रुपये, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

पटना , (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने श्मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाय् को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, बिहार के हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि यह राशि सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। यह योजना सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही सीमित नहीं है। सीएम नीतीश ने बताया कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े मिशन का हिस्सा है। पहली किस्त के 6 महीने बाद, महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार का आकलन किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उन्हें 2 लाख रुपये तक की कुल आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमलोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक और दूरगामी परिणाम होंगे। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ राज्य के हर परिवार की एक इच्छुक महिला को मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ?2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी पहली किस्त के रूप में, ?10,000 की राशि सितंबर 2025 से सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने में मदद करेगी। ?10,000 की प्रारंभिक सहायता के बाद, ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग महिलाओं के रोजगार प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर उन्हें ?2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट का महिलाओं के लिए बड़ा फैसला

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब इसी दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल राज्य के विकास में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

आतंकवाद के खिलाफ मानवता की जीत का स्वर्णिम अध्याय है ऑपरेशन सिंदूर : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई का एक स्वर्णिम अध्याय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी आकाशतीर एयर डिफेंस और रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान की तारीफ की। आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका पर बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने राजस्व और लाभ सहित प्रमुख वित्तीय मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि तीन–चौथाई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ कमा रहे हैं, और पिछले दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का शुद्ध लाभ काफी बढ़ा है।

ऑपरेशन सिंदूर में आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम की रही अहम भूमिका

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सार्वजनिक उद्योगों ने सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में मानक स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया अभियान की अहमियत पर कहा श्सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। देश के रक्षा क्षेत्र का विशेष उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि श्ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और भारत पर हमले के प्रयासों को विफल कर दिया। स्वदेशी आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम ने अचूक क्षमता का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने इस प्रणाली के निर्माण में योगदान दिया है। यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि नवाचार और भारत की बढ़ती तकनीकी विशेषज्ञता से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बड़ा योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कृषि, खनन और अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण और सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुर्मू ने आगे बताया कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक है।

एक-दूसरे को नीचा दिखाने की सस्ती राजनीति से देश का माहौल खराब ना करें : मायावती

लखनऊ, (संवाददाता)। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राजद की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मंच से कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर देशभर में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने भी इस प्रकरण पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुई अभद्र टिप्पणी की निंदा की है। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में खासकर राजनैतिक स्वार्थ के कारण राजनीति का गिरता हुआ स्तर अति–दुखद एवं चिंतनीय है। इस संबंध में सभी पार्टियों की राजनीति, पार्टी के संविधान के हिसाब से विचार और सिद्धान्तों के आधार पर, देश व करोड़ों गरीबों व आमजन के हित में होनी चाहिए, जो कि खासकर पिछले कुछ वर्षों से सही से देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इस दौरान देश के सामने विभिन्न प्रकार की आन्तरिक एवं बाहरी चुनौतियां काफी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि देश के उच्च सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं व विशेषकर राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित व असंसदीय टिप्पणी आदि सार्वजनिक तौर पर करके उनकी व देश की छवि को भी धूमिल करने के जो प्रयास किये जा रहे हैं, वह अति–दुखद व चिंतनीय है। खासकर चुनाव के समय यह प्रक्रिया और भी अधिक विषैली व हिंसक हो जाती है। इसी क्रम में अभी बिहार में भी जो कुछ देखने व सुनने को मिला है, वह देश की चिन्ता को बढ़ाने वाला है। मायावती ने आगे कहा कि बसपा शुरू से ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धान्त और नीति पर आयरन दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पार्टी व सरकार चलाने का साहस दिखाने वाली पार्टी होने के कारण किसी भी प्रकार की दूषित व जहरीली राजनीति के खिलाफ है और दूसरों से भी यही उम्मीद करती है कि वे देश व आमजन के हित में घिनौनी स्वार्थ की राजनीति करने से दूर रहें।

राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में वृद्धि : सीएम सिद्धारमैया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार एथलीटों को समर्थन देने और उन्हें अधिक ऊंचाइयां हासिल करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धारमैया ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देते करते हुए कहा, श्हमने स्वर्ण पदक विजेताओं को सात लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को पांच लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को तीन लाख रुपये देने का फैसला किया है। इन खेलों में कर्नाटक 34 स्वर्ण, 18 रजत और 28 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। सीएम ने आगे कहा, श्यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक अगले खेलों में पहला स्थान हासिल करेगा। इस दौरान सिद्धारमैया ने याद दिलाया कि 2015 में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए क्रमशः पांच लाख रुपये, तीन लाख रुपये और दो लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा, श्कर्नाटक ओलंपिक संघ ने राशि बढ़ाने का आग्रह किया था। हमने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और राशि में संशोधन किया है।श सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि एथलीटों को पदक जीतने में मदद करने वाले प्रबंधकों और कोचों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, श्सरकार राज्य में खेलों को हर संभव सहयोग देगी। मैं शुरू से ही एथलीटों की मांगों को पूरा करता रहा हूं।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पदक विजेताओं को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।

असम का नेतृत्व ऐसे लोग नहीं कर सकते, जो बार–बार पाकिस्तान जाते हों, अमित शाह

गुवाहाटी, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि असम का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में नहीं हो सकता, जो बार–बार पाकिस्तान जाते हैं। उन्होंने इशारों में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर यह टिप्पणी की, जिनके पाकिस्तान से कथित संबंधों की बात सामने आई है। यहां पंचायत प्रतिनिधियों की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने असम विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बजा दिया है। राज्य में मार्च–अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को असम का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, जो घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों से सहानुभूति रखते हैं। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकास कार्य किए हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने उन योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया है। इन विकास कार्यों के दम पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अगले साल लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि असम का नेतृत्व उन लोगों के पास नहीं होना चाहिए जो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं। गौरव गोगोई की तरफ इशारा करते हुए शाह ने कहा, असम का नेतृत्व ऐसे लोग नहीं कर सकते जो बार–बार पाकिस्तान जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा ने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया था।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ में मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) में कार्यकारी निदेशक के रूप में तीन साल के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। डॉ. पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में नोटबंदी जैसा बड़ा आर्थिक फैसला लिया गया था। इस फैसले की पृष्ठभूमि में डॉ. पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 2018 में डॉ. पटेल ने व्यक्तिगत कारणों से आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पहले ऐसे गवर्नर बने जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया और 1992 के बाद सबसे कम कार्यकाल तक आरबीआई गवर्नर रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण नीति पहल की। उन्होंने महंगाई दर की ऊपरी सीमा 4 प्रतिशत तय करने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार किया। इस नीति के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के आसपास बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आरबीआई में गवर्नर बनने से पहले डॉ. पटेल डिप्टी गवर्नर के रूप में मौद्रिक नीति, आर्थिक अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। डॉ. पटेल इससे पहले भी पांच साल तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन डीसी और फिर 1992 में नई दिल्ली में उप–स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, 1998 से 2001 तक वे वित्त मंत्रालय में सलाहकार रहे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम जैसी कई सार्वजनिक और निजी कंपनियों में भी प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई हैं।

सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना–तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। उनकी यह टिप्पणी पटना में सत्तारूढ़ दल द्वारा श्मतदाता अधिकार यात्राश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में निकाले गए एक विरोध मार्च के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद आई है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर पार्टी के सदाकत आश्रम मुख्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने श्ग्श पर एक पोस्ट में कहा, श्मतदाता अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ जनता की बढ़ती भावनाओं से बौखलाकर भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने और धमकाने के लिए अपने गुंडों को छोड़ दिया है।श उन्होंने कहा, श्पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में किया गया हमला कायरतापूर्ण कृत्य है। यह हमें नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा।

संपादकीय

भारत रूस और चीन से बढ़ा रहा संबंध

चूंकि भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार कमजोर है और अन्य देशों में तुरंत बाजार हासिल करना आसान नहीं है, तो कंपनियां उन देशों में जाने पर विचार कर रही हैं, जिन पर लगा टैरिफ भारत से कम है। डॉनल्ड ट्रंप के प्रमुख टैरिफ संबंधी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जो सख्त बातें कहीं हैं, उनका संकेत है कि निकट भविष्य में अमेरिका से भारत के रिश्ते बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। यानी ट्रंप प्रशासन के टैरिफ की मार भारत को लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। नवारो ने कहा कि भारत अगर चाहता है कि अमेरिका उससे रणनीतिक सहभागी जैसा व्यवहार करे, तो उसे अपना व्यवहार सुधारना होगा। उसे रूस से तेल खरीदने का अवसरवाद छोड़ना होगा। नवारो ने नाराजगी जताई कि ऐसा करने के बजाय अब भारत रूस और चीन से अपने संबंध और बढ़ा रहा है। मतलब साफ है। अमेरिका की सख्ती जारी रहने वाली है। यही वजह है कि कारोबार जगत में इंडिया+1 का जुमला चल निकला है। इसके पहले चीन+1 की बात चर्चित हुई थी, जब अमेरिकी सरकार ने चीन के खिलाफ व्यापार कार्रवाई शुरू की। तब अमेरिकी कंपनियों ने चीन से किसी अन्य देश में अपने कारखाने ले जाने शुरू किए। उसका कुछ लाभ भारत ने भी उठाया। मगर अब भारत निशाने पर है। तो खबरों के मुताबिक कई कंपनियां अपने कारखाने भारत से बांग्लादेश, कंबोडिया या वियतनाम ले जाने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि भारत में कारखाना उत्पादन का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी बाजार रहे हैं। पिछले साल भारत के कुल निर्यात का 18 फीसदी हिस्सा अमेरिका गया था। अब ये बाजार भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिकूल होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि चूंकि भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार कमजोर है और अन्य देशों में तुरंत बाजार हासिल करना आसान नहीं है, तो कंपनियां उन देशों में जाने पर विचार कर रही हैं, जिन पर लगा टैरिफ भारत से कम है। इसका असर अभी से भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्रों में महसूस किया जाने लगा है। आम राय है कि आने वाले महीने और भी ज्यादा चुनौती भरे होंगे। भारत के लिए यह बुरी खबर है। मगर चीन+1 की जिस पृष्ठभूमि पर भारत के आगे बढ़ने की आस जोड़ी गई थी, उसमें यह जोखिम पहले से मौजूद था। उसे नजरअंदाज करना अब भारी पड़ रहा है।

हम फिलिस्तीन को कैसे याद करेंगे

श्रुति व्यास

क्या होता है जब कोई राष्ट्र–राज्य मिट जाता है या मिटा दिया जाता हैं? सामान्य जवाब हैकृकुछ भी नहीं। कुछ दिनों तक जरूर शोर–शराबा, टूटे दिल और एकजुटता के हैशटैग चलेगें। फिर भूलने की बीमारी आ जाती है। गायब होना स्मृति के किसी कोने में दर्ज होता जाता है। सामान्य ज्ञान की किसी एक पुस्तक, एक खंड में सिमट कर रह जाता है। राजनीति में प्रतिक्रिया थोड़ी भारी जरूर होती है, लेकिन उतनी ही खोखली। बड़े–बड़े शब्दों में निंदा, और उससे भी बड़े शब्दों में पलटवार। ठंडी, रोशन कमरों में गुनगुनी चाय के बीच प्रस्ताव लिखे जाते हैं, नीतियाँ बहस में फँसी रहती हैं, बयान पढ़े जाते हैं। और फिरकृसन्नाटा। जो राज्य मिटा दिया गया, वह इतिहास और इतिहास की किताबों भर मे ही जीवित रहता है। देश–राज्य सचमुच गायब होते हैं, हो चुके हैं। 1947 से पहले कितने देश, राजा–रजवाडे थे। कईयों को अंग्रेजों ने भी सिर पर बैठा रखा था। ऐसे ही पूरी दुनिया में इतिहास भरा हुआ है। पर राष्ट्र–राज्य कभी गर्जना के साथ, कभी लगभग बिन आवाज, और कभी पूरी दुनिया की आँखों देखी मिट जात है। इतिहास हमें बताता है कि सरहदें रातों–रात खींची जा सकती हैं, हालांकि उनके परिणाम लंबे, खूनी और स्थायी भी होते हैं। और इस वक्त, एक ऐसा ही मिटाया जाने का मामला हमारी आँखों के सामने घट रहा है। आज, फिलिस्तीन को मिटाए जाने का खतरा है। इजरायल ने एक ऐसी बस्ती योजना को मंजूरी दी है, जो सिफ`कब्जे के लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीनी राज्य की धारणा को ही मिटाने के लिए बनाई गई है। यह है ई1 प्रोजेक्ट, जो पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) को दो हिस्सों में बाँट देगा और उसे पूर्वी यरुशलम से काट देगा। पिछले हफ्ते इसकी घोषणा वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने की, जो नेतन्याहू की सरकार के कट्टर राष्ट्रवादी धड़े से आते हैं। बुधवार को रक्षा मंत्रालय की योजना समिति ने इस पर अंतिम मुहर लगाई। स्मोट्रिच ने शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश भी नहीं की। उनका ऐलान थारू फिलिस्तीनी राज्य मेज से हटा दिया गया है, नारे से नहीं, बल्कि काम से। जाहिर है यह पुरानी शैली का टैंकों और संधियों वाला अधिग्रहण नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित नक्शा है। सड़कों और बस्तियों को इस तरह खींचना कि जमीन बिखर जाए और राज्य पहचान धूमिल और मिट जाए। अगर यह लागू हुआ तो ई1 प्रोजेक्ट पश्चिमी तट को उत्तर और दक्षिण में बाँट देगा, फिलिस्तीनी राज्य के फैलाव, निरंतरता मिटेगी और रामल्ला, पूर्वी यरुशलम और बेथलहम के बीच का शहरी गलियारा काट देगा। यह भूगोल के साथ धीमी हिंसा हैकृमिटाना किसी नाटकीय आघात से नहीं, बल्कि सीमेंट, जोनिंग कानूनों और जमीन पर तथ्य गढ़ने से होगा। राष्ट्र–राज्यों को मिटते हुए हमने पहले भी देखा है। 1950 में जब चीन ने तिब्बत को निगल लिया, दुनिया ने नजरें फेर लीं। बहुत दूर, बहुत जटिल, बहुत असुविधाजनक। पहाड़ों ने चीखों को दबा दिया। दुनिया का सबसे ऊँचा राष्ट्र चीन के एक प्रांत में बदल गया। मठ गोलाबारी में ढह गए, भिक्षु भूमिगत हो गए। जिन लोगों का अपना झंडा, अपनी लिपि, अपनी प्रार्थनाएँ थीं, उनसे कहा गया कि अब वे बस चीनी हैं। दलाई लामा हिमालय पार कर भारत आए। एक पल को लगा, दुनिया जाग उठेगी। लेकिन नहीं, सन्नाटा बना। होनी मान ली। तिब्बत नक्शों से मिटा दिया गया और निर्वासन में ठेल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उसे खोई हुई लड़ाइयों की श्रेणी में रख दिया। यहाँ तक कि भारतकृजिसने दलाई लामा को शरण दी, जहाँ आज भी निर्वासित तिब्बती सरकार है, उसने भी तिब्बत को भुला सा दिया है। हम इसे तभी याद करते हैं जब बीजिंग को चुभाना हो, उसके मकध्सद के लिए नहीं। धर्मशाला में युवा भिक्षुओं के मंत्र, मैक्लॉडगंज में लहराते प्रार्थना झंडेकृये सब उस संघर्ष के अवशेष हैं जिसे भारत ने भुला दिया है। निर्वासन में जन्मे तिब्बतियों के लिए उनका वतन अब सिफ`स्मृति और मिथक हैकृदादा–दादी की कहानियों में ल्हासा, गीतों में, अनुष्ठानों में जो भूगोल से आगे जीते हैं। बाकध् दुनिया के लिए तिब्बत एक पर्यटक पोस्टकार्ड है, कोई राजनीतिक घाव नहीं। यही है मिटाए जाने का तरीकारू दुनिया एक देश के बिना जीना सीख लेती है, भले ही उसके लोग उसे कभी भूलते नहीं। इतिहास सिखाता है कि जब राष्ट्र–राज्य गायब होते हैं, दुनिया उसे होनी मान लेती है, रियलिटी में ढल जाती है। व्यापार फिर शुरू होता है, कूटनीति नए हिसाब से चलती है, नकध्शे नए बनते हैं, किताबें फिर लिखी जाती हैं। कुछ बड़ा नहीं होताकृसिवाय उनके लिए जो अपना घर खो बैठते हैं। उनके लिए मिटाया जाना अंत नहीं, निर्वासन की शुरुआत है। हाँ, राज्य मिट जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। वे स्मृतियों में, निर्वासन में, प्रवासी समाज में जिंदा रहते हैं। वे पहचान गढ़ते हैं, संघर्षों को जीवित रखते हैं, बहुत देर तककृजब दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है। तिब्बती झंडे आज भी निर्वासन में लहराते हैं। दक्षिण वियतनाम आज भी प्रवासी मोहल्लों में साँस लेता है।

मोहन भागवत के तीन दिवसीय संबोधन ने दिये कई संदेश

नीरज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना को एक शताब्दी पूरी होने जा रही है। यह अवसर केवल आत्ममंथन का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगातार तीन दिनों तक इसी संदर्भ में अपने विचार रखे। उनके वक्तव्य में अतीत का आत्मविश्वास भी था और भविष्य की चिंता भी। तीन दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न केवल संगठन के अतीत और उपलब्धियों की समीक्षा की, बल्कि भविष्य की रूपरेखा और समसामयिक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। भागवत का वक्तव्य इस बात पर केंद्रित था कि संघ मात्र एक सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के विकास, संतुलन और दिशा निर्धारण का सहभागी भी है। इसके अलावा, अक्सर यह प्रश्न उठता है कि बीजेपी की राजनीति और आरएसएस का मार्गदर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन भागवत ने स्पष्ट किया कि "हम विशेषज्ञ अपनी शाखा में हैं, वे सरकार चलाने में विशेषज्ञ हैं। हम सुझाव दे सकते हैं, निर्णय उनका है।" देखा जाये तो यह कथन राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंकाओं को खारिज करता है और संघ की भूमिका को वैचारिक मार्गदर्शक तक सीमित बताता है। "अगर हम तय करते, तो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देर क्यों होती?" कृयह टिप्पणी संघ और सत्ता के बीच के संबंधों पर एक रोचक संदेश देती है। इसके अलावा, संघ प्रमुख ने दो टूक कहा कि जब तक समाज के वंचित वर्ग स्वयं महसूस न करें कि उन्हें विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है, तब तक संघ आरक्षण का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने जाति–आधारित विभाजन को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि "ऊपर वाले हाथ बढ़ाएं और नीचे वाले आगे बढ़ने की कोशिश करें।" यह दृष्टिकोण भारतीय समाज के भीतर असमानताओं को पाटने के संघीय दृष्टिकोण को सामने रखता है। साथ ही, भागवत का "हर परिवार को तीन बच्चे" वाला बयान जनसंख्या नियंत्रण की बहस में नया मोड़ लाता है। उनका कहना था कि 2.1 की औसत जन्मदर को व्यवहारिक रूप में तीन बच्चों के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि साथ ही उन्होंने संसाधनों के संतुलन और प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा, धर्म को व्यक्तिगत विकल्प बताते हुए उन्होंने कहा कि "हिंदू और मुस्लिम को एक करने की बात ही क्यों, वे पहले से एक हैंकृ भारतीय हैं।" भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम भारत में रहेगा और कोई हिंदू ऐसा सोच ही नहीं सकता कि इसे समाप्त होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आक्रांताओं के नाम पर जगहों और सड़कों के नामकरण पर आपत्ति जताई और प्रेरणादायी व्यक्तित्वोंकृ जैसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नामकरण का सुझाव दिया। साथ ही अवैध प्रवास और जबरन धर्मांतरण को उन्होंने जनसांख्यिकीय असंतुलन की जड़ बताया। उनका तर्क था कि नागरिकोंकृ हिंदू या मुस्लिम को रोजगार और अवसर मिलने चाहिए, लेकिन अवैध प्रवासियों को नहीं। इस दृष्टिकोण में राष्ट्रहित और मानवता दोनों का संतुलन झलकता है। इसके अलावा, भागवत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (।प्) और आधुनिक तकनीक के अवसरों और खतरों पर चर्चा करते हुए कहा कि "तकनीक का मालिक इंसान होना चाहिए, न कि तकनीक इंसान की नियति तय करे।" शिक्षा केवल सूचनाओं का ढेर नहीं बल्कि मनुष्य निर्माण का साधन होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में इन बातों के समावेश की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अमेरिकी दबाव की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, लेकिन मित्रता दबाव में नहीं पनप सकती। आत्मनिर्भरता और पारस्परिक निर्भरता दोनों का संतुलन बनाना भारत की विदेश नीति का आधार होना चाहिए। देखा जाये तो मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की 100 वर्षों की यात्रा से आगे के 100 वर्षों की झलक प्रस्तुत करता है। यह यात्रा केवल

संगठन की नहीं, बल्कि भारतीय समाज की भी हैकृ जहाँ परंपरा और आधुनिकता, आध्यात्म और विज्ञान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय हितकृ सबको जोड़ने का प्रयास है। भागवत का संदेश साफ है– राजनीति से दूरी रखते हुए वैचारिक मार्गदर्शन, समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता, तकनीक और शिक्षा के नए युग में भारतीय दृष्टि का समावेश और विश्व स्तर पर आत्मनिर्भर लेकिन सहयोगी भारत की परिकल्पना। बहरहाल, संघ की शताब्दी केवल एक संगठन की यात्रा नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के विकास और बदलाव की गवाही भी है। मोहन भागवत का संदेश यही था कि आने वाले समय में संघ राजनीति से परे, समाज और राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभाता रहेगा। प्रश्न यह है कि क्या संघ आने वाली पीढ़ियों को उस समन्वय और आधुनिक दृष्टि से जोड़ पाएगा, जिसकी झलक भागवत ने दिखाई है? यदि हाँ, तो संघ की दूसरी शताब्दी न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में उसकी प्रासंगिकता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।

भारत–जापान दोस्ती से नये वैश्विक संतुलन की कोशिश

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी की नई एशियाई शक्ति संरचना का संकेत है। यह यात्रा भारत और जापान के बीच 'दोस्ती के नए दौर' का आगाज है, जो वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर गहरा असर डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत–जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए जापान की टेक्नोलॉजी और भारत के टैलेंट से दोनों देशों के साथ दुनिया की तस्वीर बदलने की बात कही। भारत की विकास यात्रा में जापान की अहम भूमिका रही है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक अनेक विकास, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हमारी साझेदीरी आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। भारत विश्व की सबसे तेज विकसित होती अर्थ–व्यवस्था है। बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें दोनों देशों की निकटता से नये आयाम उद्घाटित होंगे। आज वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और चीन, अमेरिका एवं भारत के बीच चल रही 'टैरिफ वार' है। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्क ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदल दी है। इस टकराव का असर केवल अमेरिका–चीन पर नहीं पड़ा, बल्कि भारत जैसे उभरते बाजारों और विकसित होते देशों पर भी गहरा संकट आया है। भारत के निर्यात को नुकसान पहुँचा है, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता आई है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। ऐसे समय में भारत–जापान का एक–दूसरे के और नजदीक आना एक 'रणनीतिक अवसर' है। जापान तकनीक, पूँजी और नवाचार में अग्रणी है, वहीं भारत के पास विशाल मानव संसाधन, बड़ा बाजार और विकास की अपार संभावनाएं हैं। मोदी की यह यात्रा इन दोनों शक्तियों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है, ताकि अमेरिका की टैरिफ वार से बने शून्य की भरपाई की जा सके। निश्चित ही अमेरिका का भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाना भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने में भारत सक्षम भी है। इन्हीं जटिल स्थितियों के बीच भारत अपने उत्पादों के लिए नए बाजार की तलाश में है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के बाद चीन जाएंगे और वहां एससीओ समिट में भी हिस्सा लेंगे। चीन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से भी हो सकती है। मोदी की यह जापान यात्रा केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। चीन के विस्तारवाद, अमेरिका की अनिश्चित नीतियों और रूस–यूक्रेन युद्ध जैसे हालात में भारत और जापान का साथ आना 'संतुलनकारी शक्ति' की तरह काम करेगा। दोनों देशों ने 'इंडो–पैसिफिक रणनीति' को मजबूती देने पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य एशिया में शांति, स्थिरता और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। जापान भारत का पूराना मित्र राष्ट्र है। भारत और जापान के रिश्तों की नींव कोई आज की नहीं है। आठवीं शताब्दी में बोधिसेना नामक भारतीय साधु ने नारा के तोदाईजी मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की थी। यह पहला ऐतिहासिक संपर्क माना जाता है। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जस्टिस राधा बिनोद पाल जैसी हस्तियों ने दोनों देशों के रिश्तों को गहरा किया। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज को जापान से मिला समर्थन एवं सहयोग इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते सन् 1947 से पहले से ही प्रगाढ़ एवं मित्रतापूर्ण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने जापान के साथ अलग शांति संधि की, जिससे दोनों देशों के बीच आधिकारिक रिश्तों की शुरुआत हुई। आज भारत–जापान साझेदारी में रक्षा, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और रणनीतिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। मित्रता एवं सहयोग की यह विरासत आज भी जारी है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह जापान की 8वीं यात्रा है। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को 15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। मोदी की यह जापान यात्रा निश्चित तौर पर दूरगामी उद्देश्यों से जुड़ी है। दोनों देशों के साझेदारी से नयी दिशाएं उद्घाटित होंगी, हालांकि इस साझेदारी की राह आसान नहीं है। भारत को अपनी नौकरशाही जटिलताओं, बुनियादी ढाँचे की कमी और नीतिगत अस्थिरताओं को दूर करना होगा, ताकि जापानी निवेशकों का विश्वास बढ़ सके। वहीं जापान को भी यह समझना होगा कि भारत का बाजार केवल उपभोक्ताओं का नहीं बल्कि एक साझेदारी की संभावनाओं का बाजार है। अमेरिका की टैरिफ वार ने वैश्विक व्यापार को असंतुलित किया है, लेकिन भारत–जापान की साझेदारी इसे संतुलन की दिशा दे सकती है। यदि यह रिश्ता आगे बढ़ता है, तो भारत केवल जापान का साझेदार ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया में 'नई शक्ति धुरी' का केंद्र बन सकता है। भारत–जापान की निकटता एवं

आपसी समझौते अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भरपूर संभावनाएं हैं। इससे सप्लाई चेन का नया केंद्र विकसित होगा। वैसे भी जापान, चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है। भारत इसके लिए सबसे स्वाभाविक विकल्प है। यदि जापानी उद्योग भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं तो 'मेक इन इंडिया' को नई ऊर्जा मिलेगी। हाई–टेक सहयोग से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत–जापान साझेदारी एशिया की नई तकनीकी धुरी बना सकती है। यह व्यापारिक संतुलन का भी आधार है। अमेरिका और यूरोप के बाजार अस्थिर हैं। भारत–जापान मिलकर 'एशिया–प्रशांत' को स्थिर और सशक्त व्यापारिक क्षेत्र बना सकते हैं। दोनों देश बुनियादी ढाँचा निर्माण करते हुए एक दूसरे के विकास में सहायक होंगे। जापान का विशेष अनुभव और वित्तीय सहयोग भारत की मेट्रो रेल, हाई–स्पीड बुलेट ट्रेन और बंदरगाह परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि दोनों देशों को दीर्घकालिक साझेदार बनाएगा। निश्चित दौर पर मोदी की जापान यात्रा केवल दोस्ती का नया अध्याय नहीं है, बल्कि अमेरिका–चीन टकराव से उपजे शून्य को भरने की कोशिश है। यह भारत को एक 'पैसिव खिलाड़ी' से 'ग्लोबल लीडर' की भूमिका में लाने का अवसर है। भारत–जापान की दोस्ती का नया दौर बदलती वैश्विक परिस्थितियों और शक्ति–संतुलन का निर्णायक पहलू है। आज की दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अमेरिका और चीन की टकराहट ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र को विश्व राजनीति का केंद्र बना दिया है। चीन की आक्रामक नीतियां, उसके विस्तारवादी रुख और आर्थिक दबदबे की कोशिशों ने भारत और जापान को स्वाभाविक रूप से निकट लाया है। भारत–जापान की साझेदारी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर 'क्वाड' को मजबूत करती है। यह केवल सुरक्षा गठबंधन नहीं बल्कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन, आतंकवाद से मुकाबला, और आपसी व्यापार–विकास का साझा दृष्टिकोण है। इससे चीन की एकध्रुवीय शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगता है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और टैरिफ बाधाओं ने भारत–जापान को विकल्प खोजने पर मजबूर किया है। दोनों देश मिलकर 'चीन–प्लस–वन' रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी चीन पर निर्भरता कम करके एशिया और अफ्रीका के नए बाजारों में निवेश और उत्पादन केंद्र बना सकते हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संतुलित होगी। जापान भारत में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। भारत की युवा कार्यशक्ति और जापान की तकनीकी दक्षता मिलकर नवाचार और टिकाऊ विकास का मॉडल पेश कर सकती है। यह मॉडल पश्चिमी पूंजीवाद और चीनी साम्यवादी अर्थशास्त्र से भिन्न होगा। दोनों देशों के बीच संबंध केवल रणनीति या व्यापार तक सीमित नहीं हैं बल्कि साझा मानवीय मूल्यों से नैतिक गहराई प्रदान करने का आधार भी है।

राहुल को अतिरिक्तसावधानी बरतने की जरूरत

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ चुकी है। देश में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कई प्रयोजनों से यात्राएं समय–समय पर निकल चुकी हैं। लेकिन तीन साल पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजनैतिक यात्रा के नए आयाम खोले, इसे लोगों का जितना प्यार और समर्थन मिला, उसे देखकर राहुल गांधी ने फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और अब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा दोनों को लेकर भाजपा का रवैया काफी लापरवाह था, क्योंकि उसे यकीन था कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे और यात्रा बीच में ही असफल होकर रुक जाएगी। लेकिन भाजपा का अनुमान गलत निकला। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा बेहद शांति के साथ पूरी कर ली। उनकी राह में कानूनी अड़चनें डाली गईं, महिलाओं, बच्चों, पशुओं के नाम पर गंभीर आरोप लगाए गए। उनका बहुत तरह से मजाक बनाया गया। लेकिन एक भी दांव काम नहीं आया। हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद दोनों यात्राएं लगभग निर्विघ्न संपन्न हुईं। अब वोटर अधिकार यात्रा पर लोगों की नजर है। पहली दोनों यात्राएं तो दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम हुईं, लेकिन मौजूदा यात्रा का दायरा केवल बिहार के कुछ हिस्सों में सीमित है। लिहाजा पहले के मुकाबले यह और आसानी से संपन्न हो सकती है। बस इसे लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि विघ्नसंतोषी कहीं भी व्यवधान डाल सकते हैं। जैसे यात्रा जब दरभंगा पहुंची तो यहां के अतरबेल में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द कहे गए। भरी भीड़ में यह जाहिर नहीं है कि अपशब्दों का इस्तेमाल किसने किया और उसे पकड़ा गया या नहीं। लेकिन इस एक घटना पर भाजपा को राहुल गांधी पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। बता दें कि यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। इस विवाद के बाद नौशाद ने माफी मांग ली है। उनका कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं भाजपा ने एक पोस्ट में कहा है कि राहुल के मंच से मोदी को गाली दी गई। इस तरह की भाषा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि देश श्री मोदी के लिए इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा की नाराजगी से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को घेरने या उन्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका वह नहीं छोड़ेगी। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने महागठबंधन के मंच से ऐसी धृष्टता करने का दुस्साहस किया है, तो रैली में तैनात सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे। उस व्यक्ति को मंच तक आने कैसे दिया गया और फौरन पकड़ा क्यों नहीं गया। इससे पहले राहुल गांधी ने जब डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल और युद्धविराम का जिक्र किया तो उन्होंने ट्रंप–मोदी संवाद के लिए तू संबोधन का प्रयोग किया। हालांकि मूलतरू अंग्रेजी में हुई बात का अनुवाद आप भी हो सकता था, लेकिन हिंदी में थोड़ा असहज रहने वाले राहुल गांधी ने तू का इस्तेमाल किया। शायद उनके सलाहकारों ने बताया हो कि इस तरह की भाषा से जनता प्रभावित होती है, उसे नेता की ताकत या काफी हद तक दबंगई का अहसास होता है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति तो कभी दबंगई की हिमायत करने वाली नहीं रही है, जब वे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो लहजा चाहे तल्ख हो, शब्द संयमित ही रहते हैं। फिर हिंदी में यही रवैया वे क्यों नहीं अपना रहे, यह समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेता बहुत मौकों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपने विरोधियों और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए कर चुके हैं। नरेन्द्र मोदी ने तो नेहरूजी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन सभी के लिए कई अभद्र टिप्पणियां की हैं। प्रियंका गांधी के पति और बच्चों पर भाजपा ने बेजा कीचड़ उछाला है। बात–बात पर संस्कारों की दुहाई देने वाली भाजपा को इसमें कभी कुछ गलत नहीं लगा। राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना चाहिए कि भाजपा के संस्कार उसे मुबारक, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा न हो। न निजी हमले हों न भाषा का स्तर बिगड़े, वर्ना भाजपा और कांग्रेस के बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कांफ्रेंस की, उसके बाद से भाजपा वोट चोरी के मुद्दे पर

काफी विचलित दिख रही है और राहुल गांधी बेहद सधे हुए तरीके से चुनाव निष्पक्ष करने की अपनी मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब इसमें राई–रत्ती भर की चूक भी नहीं होनी चाहिए, वर्ना भाजपा तो इसी ताक में बैठी है कि किसी भी तरह इस मामले को आगे बढ़ने से रोके। बेशक वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हर जगह से गठबंधन सहयोगी यात्रा में साथ देने पहुंच रहे हैं और एक नए किस्म का भारत जोड़ो आंदोलन बन रहा है। लेकिन इससे चुनाव में वोट एनडीए की जगह महागठबंधन को मिल जाएंगे, इसकी गारंटी अब भी नहीं है। वह तभी होगी, जब कांग्रेस, आरजेडी, वामदलों के कार्यकर्ता बूथ पर सावधान और सक्रिय रहेंगे। यात्रा को 1 सितंबर को खत्म हो जाएगी। मगर उसका प्रभाव मतदान होते तक बना रहे, अब इस तरफ भी ध्यान देना होगा।

लखनऊ में तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ संपन्न, 16,897 युवाओं को रोजगार के अवसर

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह आयोजन श्रम एवं सेवायोजन विभाग, बी0सी0एस0 कन्सल्टिंग लिमिटेड और द इकोनोमिक्स टाइम्स की सहभागिता से आयोजित किया गया।इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि सलाहकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर युवा रोजगार से जुड़कर अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाए। इसके लिए सरकार देश और विदेश में रोजगार के अवसर तलाश कर युवाओं को उनसे जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना तभी संभव है, जब प्रदेश में अधिक से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित हों, अत्याधुनिक तकनीक में सहभागिता बढ़े और हर युवा के हाथों रोजगार हो।सलाहकार मुख्यमंत्री केवी राजू ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सभी जनपदों में आयोजित होने चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और सरकार का विजन "हर युवा को रोजगार" साकार हो।मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन एमकेएस सुंदरम ने बताया कि इस महाकुंभ का लक्ष्य दस हजार युवाओं को देश और विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन कुल 16,897 युवाओं को विभिन्न संस्थानों और कंपनियों के माध्यम से चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अब प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। महिलाओं को भी शिक्षा के अनुसार प्राथमिकता देते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।इस अवसर पर निदेशक सेवायोजन नेहा प्रकाश ने कहा कि रोजगार महाकुंभ जैसे कार्यक्रम युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करते हैं, जहां रोजगार देने और पाने वाले एक साथ आकर अधिक से अधिक युवाओं के हाथों में रोजगार सुनिश्चित कर सकें।इस कार्यक्रम में अपर निदेशक सेवायोजन प्रमोद पुंडीर, निदेशक बी0सी0एस0 अभिषेक भारती, इकोनोमिक्स टाइम्स से अर्पित गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और कंपनियोंध संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।रोजगार महाकुंभ के सफल आयोजन से प्रदेश के युवाओं को न केवल अवसर प्राप्त हुए हैं,।

विधायक ने पुस्तकालय के लिए दिए 2.50 लाख रुपये

लखनऊ, (संवाददाता)। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बृहस्पतिवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भेंट की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा करते हुए पुस्तकालय की जरूरत जताई। इस पर विधायक ने बार एसोसिएशन में लाइब्रेरी बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सहयोग राशि भेंट की। विधायक ने जल्द ही एसी व कंप्यूटर भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम से मुलाकात कर कचहरी परिसर के पास वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने की मांग रखने का भी भरोसा दिया।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना 350 नई परियोजनाओं के लिए 35985 लाख रुपये स्वीकृत

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 350 नई परियोजनाओं को कुल 35985 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्राचीन धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास करना और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपद अम्बेडकरनगर और अमेठी के लिए कुल 05 करोड़ रूपये की 06 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अम्बेडकरनगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में संत बाबा गोविन्द साहब की तपोभूमि मठ अहिरौली का पर्यटन विकास 75 लाख रूपये की धनराशि से किया जाएगा। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के भीटी में काली मंदिर, दिलावलपुर के पर्यटन विकास के लिए भी 75 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं।अमेठी जिले के लिए भी विभिन्न मंदिरों के पर्यटन विकास की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। विधानसभा जगदीशपुर के मुसाफिरखाना स्थित महावीर मंदिर के विकास के लिए 75 लाख रूपये, तिलोई विधानसभा क्षेत्र में बाबा लख्खा दास कुटी, सैदापुर, विकासखण्ड तिलोई के लिए 01 करोड़ रूपये, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में मुसाफिरखाना स्थित बाबा महावीर दास मंदिर के विकास के लिए 01 करोड़ रूपये तथा विलेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए 75 लाख रूपये की धनराशि मंजूर की गई है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना हेतु कुल बजट में 40 हजार लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए 35985 लाख रूपये और वित्तीय वर्ष 2024–25 की क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए 28 हजार लाख रूपये रखे गए हैं। जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल के जनपदों में स्थित प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प कर उनके आसपास बुनियादी सुविधाएं सृजित करने का प्रयास कर रही है। प्राचीन धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

शुभांशु शुक्ला की बंगलूरू वापसी संभव, शर्मा की चाय का लिया लुत्फ

लखनऊ, (संवाददाता)। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पत्नी कामना व बेटे कियांश के साथ नैमिषारण्य के अतिविशिष्ट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। सूत्रों के अनुसार वे शुक्रवार को बंगलूरू रवाना हो सकते हैं। सिटी मांटेसरी स्कूल के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को शुभांशु के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इसमें खास एमओयू को लेकर चर्चा हुई है। इसमें तय हुआ था कि एकेटीयू की ओर से सीएमएस के विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर आगे ग्रामीण, वंचित सरकारी स्कूलों और आसपास के विद्यालयों के छात्रों तक वैज्ञानिक नवाचार, उद्यमिता, एआई और रोबोटिक्स जैसे व्यावहारिक कौशलों को पहुंचाएंगे। शुभांशु ने राजधानी के मशहूर शर्मा चाय स्टॉल से चाय मंगवाई। वैसे उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है, लेकिन गीता गांधी के साथ हुई बैठक के लिए शुभांशु ने शर्मा से चाय ऑर्डर करके मंगवाई।

उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ कौशल विकास कॉन्फ्रेंस में पेश किया युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय कौशल विकास कॉन्फ्रेंस में

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने योगी सरकार द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए नवाचार, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में "कौशल भारतरू कुशल भारत" अभियान नई ऊँचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने युवाओं को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा न केवल कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करे बल्कि अपनी क्षमताओं के बल पर आत्मनिर्भर बनकर "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना को साकार करे।राज्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, आईटीआई उन्नयन योजना सहित कई अन्य कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू कर लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया है।इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केंद्र और राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोगात्मक एवं अभिसरण आधारित दृष्टिकोण को मजबूत करना था। कार्यक्रम में स्किल इंडिया कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन, उद्योग जगत से गहरे जुड़ाव, शिक्षा और व्यवसाय के एकीकरण, नवोन्मेषी वित्तीय मॉडल, डिजिटल तकनीक के उपयोग और जिला कौशल समितियों एवं जिला कौशल विकास योजनाओं की निरंतरता पर विस्तृत चर्चा हुई।कपिल देव अग्रवाल ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश ने इन पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है ।

खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को इस वर्ष भी गतवर्ष की तरह खरीफ फसलों की बुवाई और रोपाई के बाद फसल संस्तुति के अनुसार पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ निरंतर संपर्क स्थापित रखा है, जिससे उर्वरक आपूर्ति की प्रक्रिया सुचारू और समयबद्ध बनी रहे।कृषि मंत्री ने बताया कि 1 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए कुल 301 यूरिया रैक भेजे गए, जिनमें से 267 रैक जनपदों तक पहुँच चुके हैं और 34 रैक मार्ग में हैं, जो अगले 2–3 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँगे। वर्तमान में किसानों की दैनिक आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन 10 से 12 रैक भेजी जा रही हैं। 27 और 28 अगस्त को ही 18 रैक यूरिया प्रदेश के विभिन्न जनपदोंकृ बस्ती, अलीगढ़, मऊ, अयोध्या, झांसी, जालौन, सुलतानपुर, शाहजहाँपुर, कानपुर, बाराबंकी, बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बदायूँ में भेजी गई।कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि प्रदेश में उपलब्ध उर्वरक बोरियों पर लिखे "भारत यूरिया" या "भारत डीएपी" जैसे नामों से भ्रमित न हों। सभी उर्वरक समान गुणवत्ता वाले हैं और किसानों को किसी एक ब्रांड को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक का उपयोग फसलों की रोपाई और टॉप–ड्रेसिंग के अनुसार करना चाहिए और अनावश्यक भण्डारण से बचना चाहिए, ताकि सभी किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके।प्रदेश के सहकारिता और निजी क्षेत्र में 27 अगस्त तक उर्वरकों की मण्डलवार उपलब्धता 5,64,865 मी.टन यूरिया, 4,07,792 मी.टन डीएपी और 3,03,446 मी.टन एनपीके दर्ज की गई है।सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग और टैगिंग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2025–26 में अब तक 12,653 छापे, 3,385 नमूना ग्रहण, 1,047 नमूना विश्लेषण और 35 अमानक नमूने चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही 571 लाइसेंस निलंबित, 1,196 लाइसेंस निरस्त, 122 चेतावनी जारी, 15 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित, 12 दुकानें सील और 111 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से 11 आरोपियों को जेल भेजा गया।कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को केवल निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक मिलेंगे और टैगिंग या ओवररेटिंग करने वाले होलसेलर और कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

सरोजनीनगर में अवैध निर्माण कराया ध्वस्त

लखनऊ, (संवाददाता)। सरोजनीनगर तहसील के कई गांवों का बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। जल्द पूरी जमीन कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए गए। प्रॉपर्टी डीलर को एक मौका दिया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि दोबारा कब्जा होता है तो प्रॉपर्टी डीलर पर केस दर्ज कराया जाए। सरोजनीनगर के हरिहरपुर गांव में हुई जांच में सामने आया कि सरकारी गाटा संख्या 851, 867, 869, 508, 507 पर कब्जा है। प्रॉपर्टी डीलर ने बाउंड्रीवॉल बनाकर प्लॉटिंग शुरू कर दी है। इसके बाद इसे गिराया गया। निगोहां के नंदौली गांव में हिस्ट्रीशीटर ने पंचायत भवन के गेट के पास गुमटी रखकर ग्राम समाज की जमीन कब्जा रखी है। एक बार कार्रवाई की गई, लेकिन दोबारा कब्जा हो गया। अफसरों की अब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि हिस्ट्रीशीटर को सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण है। आरोप है कि तहसील के अफसरों की मिलीभगत से कब्जा हुआ है।

मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक नई, मुद्दे पुराने छाए रहे

लखनऊ, (संवाददाता)। मंडलायुक्त कार्यालय में बुधवार को हुई मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में पुराने मुद्दे व समस्याएं ही छाई रहीं। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव और बदहाल सड़कों की परेशानियों को उठाया गया। मंडलायुक्त ने संबंधित अफसरों को समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। जल निगम की संस्था सीएंडडीएस की ओर से बताया गया कि अमौसी, सरोजनीनगर और बंथरा में जलभराव की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल निकासी का काम करवाने के लिए टेंडर की कार्यवाही जारी है। इसके बाद सर्वे होगा। समस्या दूर करने में चार महीने का वक्त लगेगा। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत इन क्षेत्रों में बाउंड्रीवॉल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मार्च 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के काम के संबंध में यूपीसीडा की समिति ने बताया कि बिजली के खंभे की शिफ्टिंग के लिए भुगतान किया जा चुका है। बैठक में अधिशासी अभियंता के न होने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई।

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़

लखनऊ, (संवाददाता)। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। कोरोना महामारी में उनका योगदान अमूल्य रहा। सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए चिह्नित निजी केंद्रों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई है। शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को पीजीआई में हुई कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बातें कहीं। पीजीआई की प्रो. मंदाकिनी प्रधान और सोसाइटी की पदाधिकारी डॉ. असना अशरफ, डॉ. नैनी टंडन व डॉ. तमरीन खान ने गर्भवती महिलाओं में शिशु की गति, वजन और ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी की बात कही।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सुचा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शासनादेश के अनुसार, जिन विद्यालयों की प्रबन्ध समिति, साधारण सभा या ट्रस्ट का कोई सदस्य जीवित नहीं है या जो विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से कालातीत हैं तथा जहाँ शिक्षक–कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु एकल संचालन की व्यवस्था प्रभावी है, उनके संचालन की जिम्मेदारी अब एक नई व्यवस्थागत ढांचे के तहत होगी।माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने बताया कि 27 अगस्त, 2025 के शासनादेश के तहत ऐसे विद्यालयों का संचालन अब संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति किसी विभागीय अधिकारी (श्रेणी–2 स्तर से अन्यून) को प्रबन्धक के रूप में नामित करेगी, जो सीधे समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

प्रबन्धक का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 228 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध समिति कालातीत होने के कारण एकल संचालन की व्यवस्था लागू है। इनमें से 124 विद्यालयों में यह व्यवस्था पाँच वर्षों से अधिक समय से चल रही है।नवीन शासनादेश के बाद इन विद्यालयों में प्रबन्धकीय कार्यों के साथ–साथ परिसम्पत्तियों की देखरेख, शिक्षकों–कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त प्रकरण जैसे अवकाश, जी0पी0एफ0, पेंशन, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, अधियाचन, पदोन्नति, चयनध्प्रोन्नत वेतनमान, वरिष्ठता सूची निर्धारण, महिला कर्मचारियों के विशेष अवकाश और अनुशासनिक कार्यवाही आदि अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नामित प्रबन्धक के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे।इस कदम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पारदर्शी, उत्तरदायी और नियमित होगा, जिससे शिक्षक–कर्मचारी और छात्र दोनों के हित सुनिश्चित होंगे।

जम्मू नहीं तो सहारनपुर या अंबाला ही सही, दूसरे दिन भी निरस्त रहीं जम्मू की ट्रेनें

लखनऊ, (संवाददाता)। जम्मू में बारिश से बिगड़े हालात के बाद लगातार दूसरे दिन जम्मू के लिए यात्रियों को कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं मिली। जम्मू से भी बृहस्पतिवार कोई सीधी ट्रेन यहां नहीं पहुंची, लेकिन सहारनपुर और अंबाला से कुछ ट्रेनें लखनऊ आईं। लखनऊ के रास्ते जम्मू जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस, बेगमपुरा, कोलकाता–जम्मूतवी एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त रहीं। जम्मू से आने वाली गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भी निरस्त रही। ऐसे में जम्मू जाने वाले यात्रियों ने सहारनपुर व अंबाला तक जाने वाली ट्रेनों से यात्री की। इसके आगे की यात्रा के लिए वहां दूसरी व्यवस्था देखने की बात की। गोरखपुर निवासी शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि एक दिन पहले वह जम्मू का टिकट लेकर ट्रेन से वैष्णोदेवी दर्शन के लिए गए थे। उनकी ट्रेन अंबाला तक ही गई। आगे के लिए निरस्त की गई गई। अंबाला में कटड़ा के हालात सुनने के बाद उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं से लौट आए। जम्मू से लौटने वाले अन्य यात्रियों ने भी कुछ ऐसे ही हालात बया किए। बुधवार को जम्मू तक ट्रेन न जाने के बावजूद यात्रियों को जम्मू तक का साधारण टिकट जारी करने की

खबर अमर उजाला छपने पर व्यवस्था में बदलाव हुआ। अधिकारियों के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जम्मू का कोई भी टिकट जारी नहीं किया गया। टिकट खिड़की पर तैनात कर्मचारियों ने लोगों को जम्मू तक किसी भी ट्रेन के न जाने की जानकारी भी दी। सूचना पट्ट पर भी इसे लिखा गया। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर–1 पर हेल्पडेस्क की भी स्थापना की गई है, जहां यात्रियों को ट्रेनों के निरस्तीकरण और विकल्प के बारे में जानकारी दी जाती रही। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि जम्मू में बारिश व बाढ़ से बिगड़े हालात के कारण वहां फंसे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेल सेवा को बहाल करने के लिए बृहस्पतिवार को दो विशेष ट्रेनें जम्मू से बनारस और दिल्ली के लिए चलाई गई हैं। बनारस और लखनऊ में यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क भी शुरू की गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2026 : प्रक्रिया प्रारम्भ, परिसीमन कार्य प्रगति पर

लखनऊ, (संवाददाता)। निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2026 की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। वर्ष 2021 में सम्पन्न पंचायतीराज निर्वाचन के उपरान्त संघठित ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यकाल 26 मई 2026, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है।उन्होंने बताया कि शासन स्तर से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक नगरीय निकायों के सृजन या सीमा विस्तार पर रोक लगाने के लिए नगर विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2021 में पंचायत निर्वाचन के बाद नगरीय निकायों के सृजनध सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों का आंशिक पुनर्गठन किया गया। इस प्रक्रिया में 37 जनपदों का पुनर्गठन पूरा कर विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया गया है।पूर्व में प्रदेश में 58,195 ग्राम पंचायतें विद्यमान थीं, जिनमें से 512 ग्राम पंचायतें नगर निकायों के सीमा विस्तार के कारण समाप्त हुईं, 9 ग्राम पंचायतें नवसृजित हुईं और 2 वन टंगिया ग्रामों को ग्राम पंचायतों के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं।वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आंशिक पुनर्गठन के प्रभाव से प्रभावित ग्राम पंचायतों एवं विकासखण्डों की श्रेणीवार जनसंख्या संबंधी विवरण जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन करने हेतु शासनादेश 15 और 16 जुलाई 2025 को जारी किए गए। इसके अनुरूप आंशिक प्रभावित वार्डों का परिसीमन कार्य 3 से 5 अगस्त 2025 तक पूरा कर आपत्तियां प्राप्त की गईं और उनका निस्तारण कर प्रभावित वार्डों के गठन की प्रक्रिया जारी है।नगरीय निकायों के सृजनध्सीमा विस्तार के कारण आंशिक रूप से प्रभावित 39 जनपदों में परिसीमन कार्य निर्धारित समय–सारणी के अनुसार पूरा कर संबंधित जानकारी पंचायती राज निदेशालय को 12 अगस्त 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए थे।

केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 में तेजी लाने के निर्देश दिए

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने और परियोजना प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि स्थापित इकाइयों के सब्सिडी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (च्ड थ्डम्) योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि अन्य जिलों में भी अच्छे परिणाम सामने आएं।इसी कड़ी में, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण और रेशम विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 और पीएमएफएमई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पांच मुख्य विकास अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इन अधिकारियों में आगरा की प्रतिभा सिंह, अमेठी के सूरज पटेल, वाराणसी के हिमांशु नागपाल, रामपुर के नंदकिशोर कलाल और मेरठ की नूपुर गोयल शामिल हैं।अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पीएमएफएमई और उद्योग नीति–2023 के तहत समय–समय पर किसानों एवं उद्यमियों के प्रस्तावों का गहन परीक्षण और मार्गदर्शन किया। उनके उत्कृष्ट प्रयासों से प्रदेश में पीएमएफएमई योजना में स्वीकृति दर राष्ट्रीय स्तर के 70 प्रतिशत की तुलना में 98 प्रतिशत रही। इसके अलावा, बैंक और उद्यमियों के बीच समन्वय स्थापित कर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के माध्यम से फल और सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, रेडी टू ईटध्रेडी टू कुक खाद्य पदार्थ, अनाज और दाल प्रसंस्करण,।

बप्पा को पहनाया 51 किलो का गजरा

लखनऊ, (संवाददाता)। गणेशोत्सव के दूसरे दिन मनौतियों के राजा को 51 किलो का गजरा पहनाया गया। झूलेलाल वाटिका में श्री गणेश प्राकट्य कमेटी की ओर से किए जा रहे इस महोत्सव में रामनगरी के आचार्यों ने मंगलमूर्ति की पूजा की। शाम को हुई सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने भजनों से बप्पा का सुमिरन किया। कोलकाता के भजन गायक संजय शर्मा के गीत से शाम सात बजे सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हुआ। गिरिजा के लाल रखियो मेरी लाज रे...पग पग पर जिसने मुझे संभाला कोई और नहीं मनौतियों के राजा जैसे गीत पेश किए। इसके बाद नृत्य नाटिका का मंचन हुआ। कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि समिति की ओर से बप्पा को तरह–तरह के फूलों से बना 51 किलो का गजरा पहनाया गया। घनश्यामदास अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, शरद अग्रवाल, योगेश बंसल, अखिलेश बंसल आदि लोग मौजूद रहे।

पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में संपन्न– विशाखजी

लखनऊ, सहानुभूति समाचार आर एल पांडेय हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मभूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के अवसर पर खेल मंत्रालय भारत सरकार के आह्वान पर नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश अभय प्रसाद तथा नियंत्रक एवं जिलाधिकारी विशाख जी. के निर्देशानुसार फिट इंडिया मूवमेंट एवं खेल भावना को जागृत करने के उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा कोर लखनऊ के वार्डेनों द्वारा उपनियंत्रक रविन्द्र कुमार व चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा की अगुवाई में गोमतीनगर स्थित हॉकी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में प्रतिभाग किया गया। खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सिविल डिफेंस अधिकारी सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मनोज वर्मा द्वारा विभिन्न खेल खो खो, कबड्डी आदि गतिविधियों को वार्डन की सहभागिता से कराने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस के लिए योग करके फिट रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सिविल डिफेंस लखनऊ के डिप्टी चीफ वार्डेन गुरप्रीत सिंह सेठी, स्टॉफ ऑफिसर टू चीफ वार्डेन ऋतुराज रस्तोगी, वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक मनोज वर्मा, ऋषि कुमार, मुकेश कुमार, श्रीमती ममता रानी, श्रीमती रेखा पाण्डेय, डिविजनल वार्डेन नफीस अहमद, सुनील तिवारी, रमेश सिंह चौहान, दिनेश माथुर, आशीष कपूर, डिप्टी डिविजनल वार्डेन रामगोपाल सिंह, सुनील कर्मचंदानी, ऐश्वर्य शर्मा, मुशीर अहमद, राजेंद्र श्रीवास्तव, संतोष, अरविंद मिश्रा, के.आर. पाल, प्रथम गुप्ता सहित सिविल डिफेंस के सैकड़ों वार्डेन मौजूद रहें।

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यक्ष ने 30 प्रकरणों की जनसुनवाई की, अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी

लखनऊ, सहानुभूति समाचार गिरीश चंद्र कुशवाहा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को इन्दिरा भवन, लखनऊ स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 30 शिकायतों व पत्रावलियों की जनसुनवाई की। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की गयी तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गये। जनसुनवाई के दौरान अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता व निर्गमन प्रक्रिया पर विशेष सचिव, कार्मिक विभाग के साथ बैठक की गई। इसमें जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों पर विचार–विमर्श कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार के सेवानिवृत्ति उपरान्त देयकों के भुगतान से संबंधित मामले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के उपस्थित न होने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और प्रमुख सचिव सहकारिता को पत्र भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, सीतापुर जनपद की उमा देवी के गाँव की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में उपजिलाधिकारी, सिधौली की लापरवाही को गंभीर मानते हुए नियुक्ति विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। लखनऊ निवासी सुधा सिंह के पति स्वर्गीय आनन्द कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति उपरान्त देयकों के भुगतान न होने के प्रकरण में भी नगर विकास विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर असंतोष जताया गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएँ और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए शिकायतकर्ता को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। वहीं झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य (हिन्दी) नवीन चन्द्र पटेल से संबंधित प्रकरण का समाधान हो जाने पर आयोग ने इसे निस्तारित कर दिया। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि भविष्य में सुनवाई के दौरान सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजा जाएगा।

14वें गणेश महोत्सव में द्वितीय दिन भक्तिमय वातावरण में झूमे श्रद्धालु

कछौना(हरदोई)। 14वें गणेश महोत्सव के द्वितीय दिन माता का दरबार, गीत संगीत, मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति से श्रद्धालु रात भर भक्ति में वातावरण में झूमें। माता का दरबार, गीत संगीत, मनमोहक झांकी के प्रायोजक सर्राफा व्यवसाय छोटे शुक्ला रहे। गणेश महोत्सव के अवसर पर नगर में धार्मिक उत्सव व भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। रात को माता रानी के दरबार में भव्य झांकी सजाई गई जिसमें देवी देवताओं की मनमोहक झांकी की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई। रंग बिरंगी लाइटिंग, फूलों की सजावट और कलात्मक प्रस्तुति ने भक्तों का मन मोह लिया। रात भर जागरण में गीतकार मुरादाबाद से श्याम किशोर, कानपुर से प्रवेश शुक्ला व महिला भजन गायिका मिस्टी सिंह ने एक से एक बढ़कर भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए। जय माता दी और गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। बच्चन ग्रुप द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। झांकी में भगवान श्री गणेश की अद्भुत छटा देखने को मिली। उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न स्वरूपों की झांकियां प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर पुरुष, महिलायें व बच्चे रात भर भक्तिमय वातावरण में झूमे। कार्यक्रम में सोमेश्वर महादेव सेवादार समिति के संस्थापक नेता राव मराठा, अध्यक्ष अनूप कुमार उर्फ बबलू, नगर अध्यक्ष राधा रमण शुक्ला उर्फ पंकज, सभासदगण, रोहित अग्रवाल, विजय शुक्ला, विशाल गुप्ता, मुकेश कुमार सिंह उर्फ गोलू, आयुष गुप्ता, महामंत्री अवधेश गुप्ता, गोपाल जी गुप्ता, गणेश शुक्ला, क्रांतिवीर सिंह उर्फ रैना, व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि गुप्ता, विनय शुक्ला, आशीष गुप्ता, अमित गुप्ता बघौली वाले, पवन अग्रवाल, डॉक्टर दुर्गेश पाठक, पी.डी. टेलीकॉम संचालक हरिशरण गुप्ता, हरिओम गुप्ता, शांतनु गुप्ता, तुलसी गुप्ता, श्याम जी गुप्ता उर्फ अंशू गुप्ता, यश गुप्ता, प्रखर गुप्ता, नीलेश गुप्ता सहित प्रबुद्धजन पुरुष, महिलाओं व बच्चों ने हजारों की संख्या में जागरण का आनंद उठाया।

भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्या कर शव तालाब मे फेंका

शाहाबाद (हरदोई)। भारतीय जनता पार्टी के लापता बूथ अध्यक्ष शैलेन्द्र का शव नवें दिन नर्मदा रोड स्थित एक तालाब मे पडा पाया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या करने के बाद शव को तालाब मे फेंक दिया गया। घटना की खबर लगते ही पूरे नगर मे सनसनी व्याप्त हो गयी तथा घटनास्थल पर भारी भीड एकत्र हो गयी। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनो ने करुण क्रंदन करते हुये पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये तथा प्रभारी निरीक्षक से तीखी नोकझोंक भी की गयी। परिजनो ने कुछ मीडिया कर्मियो पर भी अपनी भड़ास निकाली। लोगो के आक्रोश तथा मौके की नजाकत को देखते हुये कई थानो की फोर्स बुलानी पडी। उल्लेखनीय है कि मृतक शैलेन्द्र के पिता रामलाल ने कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उन्होने आरोप लगाया था कि गत 21 अगस्त 2025 की रात उसके पुत्र शैलेन्द्र का मोहल्ला गढी स्थित बीयर बार मे पवन भरद्वाज निवासी मोहल्ला कटरा, मुंशी खॉ पुत्र मुस्ताक निवासी मोहल्ला मूजागढ, धीरू अवस्थी निवासी मोहल्ला चौक तथा पिन्टू पुत्र बब्लू निवासी मोहल्ला पठकाना शाहाबाद जिला हरदोई से लडाई झगडा हुआ था तब से उसका पुत्र अपने घर वापस नही आया उसे आशंका है कि इन लोगो ने ही उसके पुत्र को गायब कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस ने चारो आरोपियो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तीन आरोपियो को हिरासत मे भी लिया था जिन्हे बाद मे जमानत पर छोड दिया गया था।

दोषी का इंकाउन्टर होना ही चाहिए : रजनी तिवारी

शाहाबाद (हरदोई)। भाजपा बूथ अध्यक्ष शैलेन्द्र की हत्या से जहॉ भारी जनाक्रोश दिखाई दिया वही उत्तर प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी काफी आहत दिखी उन्होने घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियो को सबालो के कटघरे मे खडा करते हुये पूंछा कि मृतक के परिजन जिस गाडी की जांच करने को कह रहे थे उस गाडी की जांच क्यो नही की गयी। मृतक के परिजनो द्वारा दोषियो के इंकाउन्टर करने की मांग पर सहमति व्यक्त करते हुये रजनी तिवारी ने कहा कि वह भी पीडित परिवार की इस मांग से सहमत है कि दोषियो का इंकाउन्टर होना ही चाहिए। उन्होने कहा कि पांच दिन पहले जब वह शाहाबाद आई थी तब उन्हे भी चिन्ता हुयी थी लेकिन तब उन्हे पुलिस अधिकारियो ने यही बताया था कि वह प्रक्रिया मे है, सीसीटीवी फुटेज देख लिये है, जांच अच्छी दिशा मे जा रही है लेकिन नौ दिन मे भी पुलिस ढूंढ नही पायी ऐसी प्रक्रिया का क्या मतलब, इंस्पेक्टर क्या करते रहे ? रजनी तिवारी ने पुलिस अधिकारियो को निर्देशित किया कि मृतक के परिजन जिन लोगो के नाम बताये उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तथा जो दोषियो को छुडाने का प्रयास कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने पुलिस अधिकारियो से कहा कि जिसने बेटा खोया हो उसका आक्रोश स्वाभाविक है लेकिन उसके साथ बदतमीजी की जाये यह बर्दाश्त नही होगा। उन्होने पैनल से पोस्टमार्टम कराने की बात कहते हुये कहा कि यदि परिजन चाहे तो उन लोगो को भी वहां मौजूद रहने दिया जाये। प्रभारी निरीक्षक तथा चौकी इंचार्ज की शिकायतो पर उन्होने कहा कि उन दोनो पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी दोषी बचना नही चाहिए। अपराधी और अपराध मे शामिल कोई भी लोग बचना नही चाहिए। पूर्व ब्लाक प्रमुख रामनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जिसने घटनास्थल का चयन किया वह सामान्य व्यक्ति नही हो सकता। कोतवाली और तहसील से 100 मीटर की दूरी पर घटना घटित होना आश्चर्य की बात है। उन्होने कहा कि जिस घटना मे लडाई झगडा होता है, चोटे भी लगती है उन्हे पकडा भी जाता है फिर भी केश का वर्क आउट न होना गंभीर विषय है।

खड़ाऊं दौड़ का पहली बार हुआ आयोजन, दर्शकों ने की सराहना

हरदोई सहानुभूति समाचार श्राष्ट्रीय खेल दिवसश पर शहीद उद्यान स्थित कायाकल्पकेंद्रम् में चार प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई। खड़ाऊं दौड़ में डॉ वीरेश शुक्ल, सूर्य नमस्कार में दीपाली और डॉ अभिषेक पाण्डेय, बॉक्सिंग में डॉ सरल कुमार और साइक्लिंग में दीपाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्र के संस्थापक व सीनियर नेचरोपैथ डॉ राजेश मिश्र ने बताया कि खड़ाऊं दौड़ में दर्शकों ने आनंद लिया। कहा खड़ाऊं दौड़ का इतिहास नहीं मिलता। इसे पहली बार कायाकल्पकेन्द्रम् द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हर खेल का महत्त्व है।

कृषि विकसित भारत बनाने के लिए कृषि इंजीनियर्स अहम भूमिका निभाए-बृजेश पाठक

लखनऊ सहानुभूति समाचार गिरीश कुशवाहा 37वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी "कृषि इंजीनियरिंग में नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण विकसित भारत की कृषि हेतु 2047 तक का रोडमैप"इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश स्टेट सेंटर, लखनऊ द्वारा 37वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। श्री पाठक ने आयोजन में पहुंचकर दीप दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद अपने संबोधान में कहा कि कृषि सदैव भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। पहले किसानों की आय बहुत सीमित थी, परंतु समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह प्रगति कृषि इंजीनियरिंग, आधुनिक तकनीकों और सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उपमुख्यमंत्री ने कहा भारत का सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च) वर्ष 2047 तक लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 43: जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि क्षेत्र की वर्तमान वृद्धि दर 3.5: से कम है। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र को 7: की दर से बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिए कृषि इंजीनियर्स मुख्य भूमिका निभाएँ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. वी. बी. सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पहले किसानों की आय बहुत सीमित थी, लेकिन कृषि इंजीनियरिंग, आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के कारण किसानों की मासिक आय में लगभग 59: की वृद्धि हुई है। यह विविधीकृत कृषि आय, बेहतर फसल मूल्य और सहायक क्षेत्रों के योगदान से संभव हुआ है। विशिष्ट अतिथि के रूप में इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एस. डब्ल्यू. अख्तर उससस ओमघ्घ्घ्पस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर संकल्पित है। वर्ष 2015– 16 आपमें औसत मासिक कृषक परिवार की आय लगभग छ8,059 थी। सरकारी नीतियों, तकनीकी हस्तक्षेप और कृषि इंजीनियरिंग में नवाचारों के कारण किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हुई है। चर्चा में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गयारूआधुनिक

सिंचाई तकनीक प्रिसीजन फार्मिं कृषि मशीनीकरण ड्रोन व स्मार्ट तकनी नवीकरणीय ऊर्जारटआधारित उपकरण फसल प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन यह अनुमान लगाया गया कि यदि इन नवाचारों को अपनाया जाए और वर्तमान वृद्धि दर को बनाए रखा जाए तो वर्ष 2047 तक किसानों की आय वर्तमान की तुलना में 3द्4 गुना तक हो सकती है। इस अवसर पर कृषि इंजीनियरिंग विशेषज्ञों व शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आवश्यक तकनीकी सुधारों प विचार–विमर्श किया। कार्यक्रम की शुरुआ तरफत में संयोजक डॉ. जसवंत सिंह ने विषय एवं अतिथियों का परिचय कराया। यू.पी. स्टेट सेंटर के चेयरमैन श्री सत्य प्रकाश ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का सफल संचालन इंजी. के. पी. त्रिपाठी, एफ.आई.ई., एस.सी.सी. सदस्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर देशभर से आए वैज्ञानिक और अभियंता सम्मिलित हुए, जिनमें प्रमुख रहे एस. डब्ल्यू. अख्तर, कुलाधिपति, इंटेग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊय डॉ. एस. एन. झा, उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग), आई.सी.ए.आर.य डॉ. आई. एम. मिश्रा, कुलपति, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी (महाराष्ट्र)य डॉ. एम. एल. गौर, कुलपति, डॉ. सी. वी. रमन यूनिवर्सिटी, वैशाली (बिहार)य डॉ. बंगाली बाबूच, पूर्व राष्ट्रीय निदेशक (आई.सी.ए.आर.दृ एन.ए.आई.पी.)य डॉ. आर. सी. श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार)य डॉ. एन. के. दास, भुवनेश्वरय डॉ. एम. नेमिचंद्रप्पा, बेंगलुरुय इंजी. जयप्रकाश, ए.डी.जी.बी. चेयरमैन, पटनाय इंजी. वसंत पराडकर, पुणे तथा उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अभियंता। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि कृषि इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीकें विकसित भारत के सपने को साकार करने की सशक्त नींव हैं। इस अवसर पर प्रख्यात कृषि इंजीनियर्स जैसे इंजी. पी. आर. चौरसिया, पूर्व एच.ओ.डी. (लघु सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकारय डॉ. कंचन के. सिंह, पूर्व ए.डी.जी. (इंजीनियरिंग), आई.सी.ए.आर.य डॉ. अम्बरीश के. तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून तथा युवा अभियंता डॉ. डी. श्रीगिरि (अनंतपुर, आंध्र प्रदेश), डॉ. जाधव महेश लक्ष्मण (नापोली, महाराष्ट्र) एवं डॉ. सी. टी. रामचंद्र (रायचूर, कर्नाटक) को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर यू.पी. स्टेट सेंटर के मानद सचिव इंजी. विजय प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज के साथ हुआ।

अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री, तस्करी पर अंकुश लगाना आवश्यक - जिलाधिकारी

हरदोई सहानुभूति समाचार विशेष प्रर्वतन अभियान चलाये जाने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का किया गया गठनरू– अनुनय झा 06. जिलाधिकारीध्जिला मजिस्ट्रेट अनुनय झा ने बताया है कि जनपद मे अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु 06 सितम्बर 2025 तक विशेष प्रर्वतन अभियान चलाये जाने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया जाता है। उन्होने बताया है कि इस सम्बन्ध में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जिसमें टीम संख्या 01 में प्रशासन से उप जिलाधिकारी सदर, आबकारी निरीक्षक सदर एवं समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सदर होगे। इसी प्रकार टीम संख्या 02 में प्रशासन से उप जिलाधिकारी शाहाबाद, आबकारी निरीक्षक शाहाबाद एवं क्षेत्राधिकारी शाहाबाद, टीम संख्या 03 में प्रशासन से उप जिलाधिकारी सण्डीला, आबकारी निरीक्षक सण्डीला एवं समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सण्डीला होगे। टीम संख्या 04 में उप जिलाधिकारी बिलग्राम, आबकारी निरीक्षक बिलग्राम एवं समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी बिलग्राम तथा टीम संख्या 05 में उप जिलाधिकारी सवायजपुर, आबकारी निरीक्षक सवायजपुर एवं समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सवायजपुर को टीमों का गठन कर जनपद मे अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर विशेष प्रर्वतन अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त टीम अवैध मदिरा के कार्य मे संलिप्त माफियाओंध तस्करों की जो सूची तैयार उपलब्ध कराई गई है, उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैगस्टरध्गुण्डा एक्ट की कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्षमता से चेकिंग कराई जाये। प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सप नम्बर 9454466019 का प्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये ताकि आम जनता बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सके। जिन आबकारी दुकानों पर उक्त नम्बरों को अंकित नही कराया गया है, तत्काल उन दुकानों पर उक्त नम्बरों का अंकन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाये। उन्होंने कहा कि उक्त टीमें प्रत्येक दिवस दबिश करेगी। प्रभावी कार्य हेतु उपरोक्त गठित टीमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धन परिवहन निगम अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करते हुए प्रवर्तन कार्य मे यथावश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे। सभी टीमें पूर्ण मनोयोग से सम्बन्धित थाने के पुलिस बल का सहयोग लेते हुए विशेष प्रर्वतन कार्य करना सुनिश्चित करें।

नाऊ पुरवा और दयालपुर के बीच में पुलिया न बनने पर आम जनमानस में आक्रोश

हरदोई सहानुभूति समाचार रुसवायजपुर के विकास खण्ड हरपालपुर के गांव रुनाऊपुरवा व दयालपुर कि रुपुलिया का निर्माण ना होने से बच्चे ओर अन्नदाता परेशान..... गम्भीरी नदी में बाढ़ आने पर दयालपुर व नाऊपुरवा कि पुलिया डूबी ओर रुनाव पर सवार होकर आने के लिए मजबूर थे बच्चे, नाव को बंद करके बैटरी रिक्शा पर 12 किलोमीटर का चक्कर लगाकर लगभग 22 बच्चे ऑटो पर सवार हो के विद्यालय नाउ पुरवा में पहुंच रहे। बीच में अधूरी पढ़ाई ना छुट जाए इसलिए ऑटो का सहारा ले रहे बच्चे शासन प्रशासन ने पुलिया बनवाने जो वादे किए वो सब हवा हवाई साबित हो रहें हैं। लगातार सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो वायरल है लेकिन शासन और प्रशासन पुलिया बनवाने हेतु कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ लगातार जअ चौनलों पर प्रकाशित खबरें शासन और प्रशासन की आंख खुलने का काम कर रही है लेकिन शासन प्रशासन कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल है लेकिन शासन प्रशासन ने दयालपुर व नाऊपुरवा कि पुलिया का निरीक्षण करना जरुरी नहीं समझा, हर बार बच्चों और अन्नदाताओं को बताया जाता है। कि चूक विभाग को कउ साहब के जरिए पत्र भेजा गया है। हर बार पत्र भेजा जा रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिया ना बनने से बच्चे और व्यपारी और किसान बहुत ही परेशानियां झेलने के लिए मजबूर है।

खेल प्रतियोगिता सुभाष चन्द्र बोस पी जी कालेज कहली तेरवा गौसगंज में आयोजित हुई

मेरा युवा भारत हरदोई युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिता सुभाष चन्द्र बोस पी जी कालेज कहली तेरवा गौसगंज में आयोजित हुई जिसमें मेजर ध्यानचंद की फोटो पर माल्यार्पण स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर अविनाश कुमार पाल सर ने करके खेल की शुरुआत करवाई बालिका वर्ग कबड्डी में बाला जी बेहंदर टीम विजेता रही और पाठशाला टीम उपविजेता रही वालीबाल पुरुष वर्ग में पाल्हाराई विजेता रही और सुभाष चन्द्र बोस पी जी कालेज की टीम उपविजेता रही कार्यक्रम के सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र के साथ मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उपविजेता को मेडल और प्रमाण पत्र दिया गया कार्यक्रम मे रेफरी की भूमिका सुभाष चन्द्र बोस पी जी कालेज के पी टी आई मिलन कुमार और संतोष कुमार इंटर कालेज बेहंदर के पी टी आई। परशुराम जी ने दोनों ने मिलकर गेम सम्पन्न कराए मुख्य अतिथि के रूप महाविद्यालय डायरेक्टर इंजीनियर अविनाश कुमार पाल , प्राचार्य डॉ डी एन सक्सेना द्द, पाठशाला प्राचार्य गार्गी श्री वास्तव जी रहीकार्यक्रम का संचालन मुदुल अवस्थी ने किया और कार्यक्रम आयोजक आसिम अली ने सभी मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर सम्मानित किया

बदहाल पड़ी सड़कों को लेकर एआईएमआईएम ने सौंपा नगर आयुक्त को ज्ञापन

प्रयागराज, (संवाददाता)। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि बारा रबीउल अव्वल पर्व को लेकर सड़कों पर निकलने वाले जुलूसों को ध्यान में रखते हुए जी0टी0बी0 नगर करेली के अंतर्गत मुख्य सड़क पहलवान तिराहा से बैंक आफ बड़ौदा, सोलह मार्केट होते हुए मस्तान मार्केट करामत की चौकी तक रिद्धि सिद्धि रोड से सोलह मार्केट तक सड़कें अत्यंत खस्ताहाल है। बडे बडे गड्ढे हो गये हैं आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है।

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय हरदोई में राष्ट्रीय खेल दिवस का शानदार आयोजन

हरदोई । सहानुभूति समाचार पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय हरदोई में राष्ट्रीय खेल दिवस का भव्य समारोह बड़े ही जोश, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह गौरवशाली दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित था, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ, मेजर ध्यानचंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस सम्मानजनक शुरुआत के बाद, सभी शिक्षकों और 727 विद्यार्थियों ने मिलकर शफिट इंडियाश की शपथ ली। इस शपथ के माध्यम से सभी को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। घ्शारीरिक शिक्षा शिक्षक श्री नवींद्र कुमार ने मेजर ध्यानचंद जी के अद्भुत जीवन, उनकी उपलब्धियों और भारतीय हॉकी में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि कैसे मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से हम अनुशासन, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सीख सकते हैं। घविद्यालय के प्राचार्य श्री मोहम्मद राशिद ने अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन में खेल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ष्खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेल हमें टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने की भावना सिखाता है।ष उन्होंने छात्रों से खेलों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह करते हुए ष्खेलेगा देश, खिलेगा देशष का नारा दिया, जिससे बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। घ्इस अवसर पर विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें स्टाफ बनाम छात्र वॉलीबॉल मैच, रोमांचक रस्साकसी प्रतियोगिता, बाधा दौड़, योग, शतरंज, कबड्डी, खो–खो, टेबल टेनिस और कई मनोरंजक खेल शामिल थे। इन प्रतियोगिताओं में कुल 727 छात्रों (400 लड़के और 327 लड़कियां) और 40 स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। घ्पूरे कार्यक्रम का सुचारु रूप से नियोजन प्रभारी श्री नवींद्र कुमार जी ने किया। इस शानदार आयोजन को सफल बनाने में श्री इलियाश, श्री आदेश, श्री सुनील, श्री अवधेश, श्री आदर्श और श्री अरुण जी का विशेष योगदान रहा। यह आयोजन न केवल मेजर ध्यानचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी, बल्कि इसने विद्यार्थियों को खेल और फिटनेस के प्रति भी जागरूक किया।

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में सुनी 73 शिकायतें

हरदोई सहानुभूति समाचार कलेक्ट्रेट कक्ष में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 73 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पैमाइश व अंश निर्धारण के प्रकरणों के निस्तारण में देरी न की जाये। भूमि विवाद के स्थायी समाधान के लिए थाकबंदी के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराया जाये। चकरोड व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाये। आज जनसुनवाई मे 02 बच्चों को बाल सेवा योजना से जोड़ा गया तथा 04 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। जन सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी वि0रा0 प्रियंका सिंह, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला पंचायत की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी आई सामने

हरदोई सहानुभूति समाचार 15 वां वित्य आयोग टाइड ग्रांट योजना के अंतर्गत 2023 मैं सुरसा थाना परिसर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था कई लाखों की लागत से बनवाये गये शौचालय कुछ ही दिनों में ही जर्जर हो गया बताते चले कि जिला पंचायत द्वारा बनवाया गया शौचालय ठेकेदारों की मनमानी के चलते घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया जिसके चलते कुछ ही दिनों में उपयोग लायक नहीं रहा निर्माण कार्य के दौरान शौचालय का टैंक भी नहीं बनाया मजे की बात तो यह है।

सहानुभूति
(हिन्दी दैनिक)

स्वामी, प्रकाशक, एवं मुद्रक गिरीश चन्द्र कुशवाहा द्वारा मंगलम प्रिंटर्स एण्ड स्टेशनर्स डी–6 नगहेटा इंडस्ट्रियल स्टेट हरदोई उ0 प्र0 से मुद्रित कराकर ऑफिस, जिदपीर चौराहा उ0 प्र0 से प्रकाशित।

स्थानीय सम्पादक
गिरीश चन्द्र कुशवाहा
मो0 नं0 9415174883

समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र हरदोई होगा।